

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2245
जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है।
21 फाल्गुन, 1946 (शक)

पीएमजीदिशा के तहत प्रशिक्षित लाभार्थी

2245. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गोरखपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या क्या है;
- (ख) ग्रामीण आबादी, विशेषकर के दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) जिला में योजना के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां हैं और इनके समाधान के क्या उपाए किए गए हैं;
- (घ) गोरखपुर में व्यक्तियों के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए स्थानीय संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ साझेदारी संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) गोरखपुर में नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन को बढ़ाने पर पीएमजीदिशा का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): प्रधानमंत्रीग्रामीणडिजिटलसाक्षरताअभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) की शुरुआत उत्तरप्रदेशकेगोरखपुरजिलेसहितराष्ट्रव्यापीस्तर पर 6 करोड़ग्रामीणपरिवारों (प्रतिपरिवारएकव्यक्ति) मेंडिजिटलसाक्षरताका प्रसार करने के लिए की गई थी।योजनाकेतहतप्रशिक्षणऔरप्रमाणनआधिकारिकतौरपर 31 मार्च, 2024 कोसंपन्नहुआ।यहयोजनासीएससीई-गवर्नेंससर्विसेजइंडियालिमिटेडद्वारादेशभरकी 2.52 लाखग्रामपंचायतोंमेंफैले 4.39 लाखसामान्यसेवाकेद्रोंकेमाध्यमसेलागूकीगईथी।देशभरमें 6 करोड़व्यक्तियोंकी तुलना में 6.39 करोड़व्यक्तियोंकोप्रशिक्षितकियागया।

पीएमजीदिशायोजनाकेतहतउत्तरप्रदेशकेगोरखपुरजिलेमें कुल 2,56,870 उम्मीदवारोंकोप्रशिक्षितकियागयाथा।इसकेअलावा, डिजिटलसाक्षरतापाठ्यक्रम (डीएलसी) योजनाकेतहतपिछले 03 वर्षोंमें 05 मार्च 2025 तकगोरखपुरजिलेमेंकुल 18,964 उम्मीदवारोंकोप्रशिक्षितकियागयाहै।

(ग) और (घ): डिजिटलसाक्षरताप्रशिक्षणकीप्रभावकारिताकोबढ़ानेकेलिए, राष्ट्रीयइलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीसंस्थान (नाइलिट) नेउत्तरप्रदेश (गोरखपुरकोछोड़कर) औरगोरखपुरमेंक्रमशः 4101 और 59 सुविधाकेंद्रस्थापितकिएहैं।

(ड.): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 79वें दौर (जुलाई, 2022 से जून, 2023) में 'व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण' (सीएएमएस) संचालित किया। सर्वेक्षण के अनुसार, 15-24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में से लगभग 78.4 प्रतिशत ने संलग्न फाइलों (जैसे, दस्तावेज, चित्र, वीडियो) के साथ संदेश भेजने (जैसे, ई-मेल, संदेश सेवा, एसएमएस) के कौशल के निष्पादन की सूचना दी। इसके अलावा, लगभग 94.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और लगभग 97.1 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास टेलीफोन और/या मोबाइल फोन हैं। उक्ति रिपोर्ट से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट-फोन के उपयोग, इंटरनेट पैठ और डिजिटल जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया था।

इसके अलावा, पीएमजीडिशा योजना के प्रभाव का विश्लेषण तीन एजेंसियों यानि आईआईटी दिल्ली, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया था। पीएमजीडिशा योजना का नवीनतम प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आईआईपीए द्वारा आयोजित किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट का सार यह है कि पीएमजीडिशा अपने बड़े पैमाने और दूरस्थ रूप से संचालित परीक्षाओं के उपयोग के कारण एक अनुठी योजना है। पीएमजीडिशा के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों को अपनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचना और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक अपने प्रतिभागियों की पहुंच को सक्षम करके उन्हें लाभान्वित किया है, जिससे देश में समग्र डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद मिली है।
